ग्लोबल स्वरूप ले चुका बिरोहर का गांव

गुमला जिला के बिसुनपूर से 8 किलो मिटर अन्दर बिरहोर का एक टोला पगडंडी से हो कर जहनगुटूआ में बसा है आदिमजनजाति बिरहोर के एकलवता टोला जिसमें 35 से 40 घर,

आलोका,
रांची सीएसडीएस/यूएनडीपी फेलोसिप के तहत

आदिमजनजाति बिरहोर ने कड़ी मेहनत से बदल दिया अपनी बिरहोर टोली का जीवन 1955 में समय से ये आदिमजनजाति गुमला के जहनगूटूआ पंचायत हेलता बिषूनपूर के 5 कि0 मि0 अंदर के गांव में निवास करते है। उस वक्त वन छोड़कर उनके पास जीविका का कोई आधार नहीं था। वन घना और वन जीव के संख्या वन के अंदर अधिक थी। लोग शिकार मारने के कला से प्रंगत थे वन से फल फूल तोड कर अपनी आजीविका चलाते थे। घर गुगू पतों से बना कर रहते है अपनी तमाम परम्परागत व्यवस्था के साथ अपने समूदाय के साथ जीवन यापन करते थे। वन माफियाओं का वन में लक्ड़ी का दोहन तेजी से होने लगा वन कटने लगे और वनजीव कम पड़ने लगे ऐसे स्थिति में उनके पास जीविका का संकट उत्पन्न हो गया गांव में लोगो ने पलायन करना शुरू कर दिया। स्थिति यहां तक आ पहुंची की आदिमजनजाति बिरहोर के भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गयी। अपने समय के संघर्श के साथ कडी मेहनत से बिरहोर समूदाय ने अपने जीवन में बदलना शुरू किया। 1981– 82 आते आते बिरहोर समूदाय वन से निर्भरता समाप्त कर दी और श्रम कि निर्भरता की ओर बढ़ते चले गये। अपने पूर्वजों के बल पर अपने गांव को सजाना सवारना शुरू कर दिया। विकास भारती ने बिरहोर समूदाय से सम्पर्क कर उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार से गुहार लगाई और सरकारी योजना बिरसा आवास से उनकी मुलाकात हुई बिरहोर अब वो पते वाला घर में नहीं रहते है उनका घर मिटटी का बन चुका है वे छोटी छोटी जमीन पर घान का उत्पाद के साथ जानवर रखने लगे है। युवा वर्ग मजदूरी करता है। महिलाए घर और रस्सी बनाने के काम करती है बुर्जूग मवेषी चराने जंगल में जाते हैं अपने गांव में खाने वाले पेड़ पौधो के बारे में जानकारी हासिल कर उन्हे अपने हित के लिए प्रयोग करना शुरू किया। गांव की दषा सुघरी और गांव के बाहर लोगो का सम्पर्क हुआ। बिरहोर समूदाय अब अपने लिए सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए ब्लॉक कार्यालय जाते है। गांव में मिटटी का घर और मवेशी और छोटी खेत के अलावा श्रम बेचना रस्सी बना कर बाजार में बेचना उनका पेशा हो गया है।

जेहनगुटूआ में जाने के कम पर पता चला कि बिरहोर समूदाय के पास घर के अलावा उनके जीने खाने के लिए उनकी जरूरत की सभी कुछ है पर उस पर मालिकाना हक नहीं है कुछ लोगो को सरकार की ओर से वन भूमि पर पटटा दिया गया है नये परिवार को नजरअंदाज किये हुए है बिरहोरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए एक आंगनबाडी की स्थापना कर दिये गये है जिसमें बिरहोर समुदाय की एक महिला वहां बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है जिसमें 40 बच्चे है बच्चे उस आंगनबाडी को खीचडी स्कूल

बोलते है। गांव में सर्वशिक्षा अभियान के तहत 5वां कलास तक के बच्चें के लिए स्कूल की व्यवस्था करनी है वह नहीं हो पाया है 1 कि0 मी की दूरी में आदिमजनजाति के आवासीय विधालय है जिसकी स्थिति र्जजर है। बिरहोर अपने श्रम बेच कर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए 4 से 6 कि0 मी0 पैदल पढ़ाने भेजते है। जिससे गांव में संजय बिरहोर एक साल पहले सीआरपीएफ में गया है अभी चैन्य में है। गांव का रोलमॉडल है गांव का पहला लड़का को अपने मेहनत के बल पर सरकार ने नौकरी दिया हैं जबकि 2008 में राज्य सरकार ने आदिमजनजाति समुदाय के षिक्षित लोगो को सीधे नियुक्ति का प्रवधान किया गया था जिससे गुमला को डीसी ने पूरा आज तक नहीं कर पाये है। बिरहोर कॉलनी में बलदिना बिरहोर बी ए फाइनल की छात्रा है और मरकिन बिरहोर इंटर तक पढ चुकी है सलेम बिरहोर मैटिक कर के घर में है। इनको नौकरी नहीं मिली है।

गांव के विजय बिरहोर ने बताया कि सरकार डीसी और डीडीसी बिरहोर का विकास नहीं चाहते है वे चाहते तो गांव षिक्षित युवाओं को नौकरी मिलती। यहां की डीसी ने पूरे गुमला में एक भी बिरहोर को सरकारी नौकरी नहीं दिया है। लम्बे समय से 32 कि0लो0 चावल और 4 लिटर मिटटी तेल दे रही है परिवार बढ रहा है वन भूमि पर पटटा नही दिया। हमारे पास परिवार चलाने के लिए श्रम बेचने के अलावा कोई दुसरा कोई विकल्प नहीं है चावल लाने के लिए हमें खुद भाड़ा लग जाता है। वनभूमि में दावा पत्र भरने के लिए ब्लॉक कार्यालय जाना पड़ता है उसके लिए भी र्खच करना पडता है एक दिन में सरकार काम नहीं करती है। और सरकार वन भूमि दे भी देगी तो सिचाई के लिए पानी कहां से लाएगे। बिरहोर कॉलनी में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य समस्या आने पर खुद से इलाज के लिए बाहर निकल कर इलाज कराते है।

जितेन्द्र पाहन बिरहोर टोली सामाजिक काम के साथ जूडे है उन्होंने बताया कि बिरहोर के नाम पर कई योजना चलती है सरकार के उदासीन रवैया के कारण इसका लाभ बिरहोर समूदाय नहीं उठा पा रहे। बिरहोर के पास भोजन का संकट है वे दिन भर मेहनत मजदूरी कर जीवन चला रहे है। आदमी का एक मात्र जरूरत चावल नहीं एक आदमी के जीवन में कई जरूरत है जिसकी पूर्ति का एक छोटा सा भाग भी सरकार पूरा करती तो बिरहोर को दिषा मिलता पर सरकार ने कभी चाहा ही नहीं।

बिरसा आवास बिरहोर की जरूरत है तो समस्या भी-

आदिम जनजाति के बिरहोर समूदाय को बिरसा आवास मिला। जिनका आवास पक्का का उसके लिए अ बवह समस्या बन गया है आवास टूट फूट हो जाए तो उनके पास सिमेट बालू लाने के लिए पैसा नही है वे किसी तरह मिटटी से उसे मरम्मत करते है। बारिश और ठंड में समस्या हो जाती है ऐसी स्थिति में खपड़ा और मिटटी के बने घर ज्यादा उपयोगी है। सरकार इन दिनों टीन के चदरा के सीट छत पर डाल रही है जिससे गरमी के दिनों में गरमी अधिक लगता है। बारिश के दिनों में आवाज अधिक आते है और ठंड के दिनों में ठंड अधिक लगते है। बिरहोर के घर बनता जरूर है पर उसका समय – समय पर मैंनटेनेस नहीं होता है। जिससे कई बिरहोर के घर टूट–फूट गया है। बनाने का प्रावधान नहीं है।

बिरहोर महिला की स्थिति सबसे दयनीय

मंजू बिरहोर, मंजू बिरोहर, सरस्वती बिरहोर, रीमा बिरहोर, से करीब 2 घंटे तक बातचीत के कम में उसने अपने समुदाय की औरतों की स्थिति के बारे में बताया कि हम अपने समूदाय में रहते है हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है हमारे पास पूरे दिन और आधी रात का काम होता है। अपने घर के बच्चों के लालन पालन के अलावा जंगल से वन उत्पादन को लाकर घर में जमा करते है। घर के लिए खाना बनाना घर की सफाई पति का देख भाल के अलावा घर का खर्च चलाने के लिए औरते रस्सी बना कर परिवार को सहयोग करती है। औरते दिन के खाली समय में सिमेंट के बोरा का जमा कर उससे रस्सी बनाने का काम करते है जिसे सप्ताहिक हाट मे बेच कर दिनभर में 70 से 80 रूप्ये कमाते है इससे कभी कभी साग सब्जी के अलावा बच्चों के कपडे दवा और कुछ अन्य जरूरी समान खरीदते है।

चुनाव नहीं जानती है पर मंजू बिरोहर सरस्वती बिरहोर रीमा बिरहोर और गांव की सभी महिलाएं चुनाव आने पर वोट डालने सभी जाती है पर उन्हों नहीं पता कि सरकार क्या होती है सरकार का का मतलब वे ब्लॉक कार्यालय ही जानते है। प्रधानमंत्री कौन है झारखण्ड राज्य का मुख्य मंत्री कौन है। इनका कहना है हम पढ़े नहीं है इसलिए जानते नहीं है शायद राजनीतिज्ञ को जानने के पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इन लोगो ने कहा चुनाव के समय आने से गांव में चर्चा होती है और स्कूल में जाकर वोट डालते है पर मेरे वोट से क्या होता नहीं जानती है। इन महिलाओं की बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं इनकी दुनिया जंगल और घर है इसके अलावे अपने मा के घर जाते है मां के घर से वापस अपने पति के घर आती है। इन लोगो नहीं जानते है रांची कहां है। गांव में रांची की चर्चा होती है पर वह कहा है नहीं पता औरतों के अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं। गांव से बाहर निकलती नहीं। गांव के ग्राम सभा होती है वहां जानते है पर कुछ नहीं बोलती है। उनका मानना है ग्राम सभा हमारी बातो को नहीं सुनेगी।

युबाओ के बल पर टीका है बिरहोर का जीवन-

10 से 12 युवाओं का एक समूह जेहनगुटूआ में है ये युवाओं के कम शिक्षित है कॉलेज की दुरियऔर आर्थिक तंगी के ने उसे हाई स्कूल और कॉलेज का मूंह नहीं देखा। घर में खाने की समस्या है जिसकी पूर्ति के लिए वे आने श्रम को बेच कर परिवार चलाने में मदद करते है। श्रम की सारी शक्ति युवाओं के उपर है। युवाओं ने गांव के लिए श्रम कर रहे उन्हें टेक्टर चलाने का काम सीख लिया है। दूसरे के खेतों में हल चलाने का काम सिख लिया है वे दिन भर गांव से बाहर टेक्टर चलाकर पैसा कमाते है। जहेनगुटूआ में 8 से 10 युवा है। जो इस तरह के काम में जुटे हुए है। प्रति दिन टेक्टर चलाने का काम करते है उन्होंने यह काम इस लिए चुना की इसमें लोगो से सम्पर्क के साथ तकनीकी ज्ञान हो सकेगा साथ में अपने लिए रोजगार के साधन है।

आंगनबाड़ी के 40 बच्चों का भविष्य अंधर में -

जेहनगुटूआ में सरकार ने आंगनबाडी केन्द्र की स्थापना कर दी है। जहां बिरहोर के 40 बच्चे आते है। ये बच्चे 3 साल बाद क्या करेंगे इनके माता पिता को नहीं पता है गांव से सरकारी स्कूल की दूरी 4 कि0 मी0 है। बच्चे को सरकारी स्कूल मे पढाने के लिए प्रतिदिन 5 रू0 भाड़ा खर्च करना पडेगा यह 5 रूप्ये कहा से आएगे। यह सवाल विजय बिरहोर के दिमाग और मन में है। अपने बच्चे को पढाना चाहते है संजय बिरहोर के 3 बच्चे है इनको स्कूल में पढाने की इच्छा पर 4 कि0मी0 की दूरी बच्चे तय नही कर पायेगे वहां बच्चे को पहुंचाना पड़ेगा जिसके लिए हमारे पास साघन नहीं है। आने वाला पीढी भी षिक्षा से वंचित ही रहेगा। संजय बिरहोर बताते है हम जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगे अपने बच्चों को षिक्षित नही कर पाएगे।